मिर्ज़ा अली अकबर काशानी

बनाम

संयुक्त अरब गणराज्य और अन्य

5 अगस्त, 1965

[पी. बी. गजेन्द्रगडकर, सी. जे., के. एन. वांचू, एम. हिदायतुल्ला, जे. सी. शाह और एस. एम. सिकरी, जे. जे.]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908, धारा 86(1) - विदेशी राज्य के खिलाफ मुकदमा - केंद्र सरकार की सहमति, चाहे आवश्यक हो - 'किसी विदेशी राज्य का शासक' क्या धारा के प्रयोजन के लिए विदेशी राज्य से अलग है।

अपीलार्थी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के मूल पक्ष में प्रत्यर्थियों के खिलाफ अनुबंध के उल्लंघन के लिए मुकदमा दायर किया। पहला प्रत्यर्थी संयुक्त अरब गणराज्य था जबकि दूसरा प्रत्यर्थी इसके विभागों में से एक था। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 86 (1) के तहत केंद्र सरकार की सहमति प्राप्त किए बिना मुकदमा दायर किया गया था। लेकिन उच्च न्यायालय ने लेटर्स पेटेंट के खंड 12 के तहत अपीलार्थी को अनुमति दे दी। प्रत्यर्थियों ने उपस्थिति दर्ज की लेकिन दावा किया कि लेटर्स पेटेंट के खंड 12 के तहत अनुमति रद्द कर दी जाए और वाद खारिज कर दिया

जाए। उनका तर्क यह था कि यह मुकदमा अक्षम्य था क्योंकि यह मुकदमा वास्तव में संयुक्त अरब गणराज्य के शासक के खिलाफ था और इसे दायर करने से पहले धारा 86 (1) के तहत केंद्र सरकार की सहमति आवश्यक थी। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 एक संप्रभु राज्य था और इस तरह उसे भारत के नगरपालिका कानून द्वारा अपनाए और लागू किए गए अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियमों के तहत मुकदमा चलाने से पूर्ण छूट प्राप्त थी। विचारण न्यायालय ने इनमें से किसी भी तर्क को स्वीकार नहीं किया और अपीलार्थी के पक्ष में डिक्री पारित कर दी। प्रत्यर्थियों ने लेटर्स पेटेंट के तहत उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच में अपील की। डिवीजन बेंच विचारण न्यायालय से सहमत थी कि धारा 86(1) अपीलार्थी के मुकदमे पर लागू नहीं है क्योंकि उक्त धारा किसी विदेशी राज्य के शासक को संदर्भित करती है, न कि किसी विदेशी राज्य को। इस संबंध में उच्च न्यायालय ने कहा कि केवल राजशाही राज्य के मामले में ही शासक को राज्य के समान माना जा सकता है। हालाँकि, अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत प्रतिरक्षा के आधार पर प्रत्यर्थी की वैकल्पिक याचिका पर, डिवीजन बेंच ने विचारण न्यायालय से अलग रुख अपनाया और प्रत्यर्थियों के पक्ष में फैसला किया। परिणामस्वरूप, अपीलार्थी का दावा खारिज कर दिया गया। उच्च न्यायालय से प्रमाण पत्र लेकर अपीलार्थी इस न्यायालय में आया।

अभिनिर्धारित किया गया: (i) प्रक्रिया के तौर पर किसी विदेशी राज्य के शासक और जिस विदेशी राज्य का वह शासक है, उसके बीच तीव्र अंतर करना स्वीकार्य नहीं होगा। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि धारा 87 में प्रावधान है कि जब किसी राज्य का शासक मुकदमा करता है या उस पर मुकदमा चलाया जाता है, तो मुकदमा राज्य के नाम पर होना चाहिए। यह भी उल्लेखनीय है कि यद्यपि धारा 84-87 बी का शीर्षक किसी भी रूप में विदेशी राज्यों को संदर्भित नहीं करता है, धारा 84 किसी विदेशी राज्य को सक्षम न्यायालय में मुकदमा लाने का अधिकार देती है; स्पष्ट रूप से विधायिका ने यह नहीं सोचा था कि किसी विदेशी राज्य के मामले को धाराओं के इस समूह के शीर्षक के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा। [328 ई.]

(ii) धारा 86, धारा 84 का प्रतिरूप है। जबकि धारा 84 किसी विदेशी राज्य पर मुकदमा करने का अधिकार प्रदान करती है, धारा 86(1) वस्तुतः विदेशी राज्यों पर मुकदमा दायर करने का दायित्व थोपती है। विदेशी राज्य ऐसे राज्य के शासक या ऐसे राज्य के किसी भी अधिकारी को उसकी सार्वजनिक क्षमता में निहित निजी अधिकार को लागू करने के लिए धारा 84 के प्रावधान के अनुसार मुकदमा कर सकता है। इस संदर्भ में 'निजी अधिकार' से तात्पर्य उन अधिकारों से है जिन्हें किसी विदेशी राज्य की नगरपालिका अदालतों में लागू किया जा सकता है, जो कि राजनीतिक

या क्षेत्रीय अधिकारों से अलग है, जिन्हें राज्यों के बीच समझौते द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत तय किया जाना चाहिए। एक समकक्ष के रूप में, धारा 86(1) विदेशी राज्यों के खिलाफ सीमित दायित्व निर्धारित करने के लिए आगे बढ़ती है। पहली सीमा यह है कि केंद्र सरकार की सहमति के बिना ऐसा मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। दूसरी सीमा यह है कि केंद्र सरकार तब तक सहमति नहीं देगी जब तक ऐसा न लगे कि मामला धारा 86(2) के किसी एक खंड (ए) से (डी) के अंतर्गत आता है। मुकदमा चलाने के लिए इस सीमित दायित्व का प्रावधान करने के बाद, विधानमंडल ने केंद्र सरकार की सहमति के बिना, किसी विदेशी राज्य के शासक को गिरफ्तारी से बचाने का ध्यान रखा है और निर्देश दिया है कि ऐसे किसी भी शासक की संपत्ति के खिलाफ कोई डिक्री निष्पादित नहीं की जाएगी; यह धारा 86(3) का प्रभाव है। यहां जो छूट दी गई है वह स्वयं शासक की अलग संपत्ति है, न कि राज्य के प्रमुख के रूप में शासक की उचित संपत्ति। [332 बी-एच]

हाजो मनिक बनाम बर सिंग, 11 खंड 17, का उल्लेख किया गया है।

(iii) जब धारा 86(I) किसी विदेशी राज्य के शासक को संदर्भित करती है, तो यह संदर्भित करती है उक्त राज्य के संबंध में शासक, और इसका मतलब वह व्यक्ति है जो उस समय केंद्र सरकार द्वारा उस राज्य के प्रमुख के रूप में मान्यता प्राप्त है। धारा 87 (1)(बी) में 'शासक' की

परिभाषा को ध्यान में रखते हुए इस तर्क को स्वीकार करना मुश्किल है कि धारा 86(1) के तहत 'विदेशी राज्य के शासक' की व्याख्या केवल निम्नलिखित मामलों में ही की जा सकती है। विदेशी राज्यों के शासक जो राजतंत्रीय सरकार द्वारा शासित होते हैं। परिभाषा को ध्यान में रखते हुए, जब धारा 86(।) विदेशी राज्य के शासकों को संदर्भित करती है, तो यह सभी विदेशी राज्यों के शासकों को संदर्भित करती है, चाहे उनकी सरकार का कोई भी रूप हो, चाहे वह राजतंत्रीय हो या गणतांत्रिक। [330 एच-331 ए]

इसके अलावा, सिद्धांत पर, ऐसा कोई कारण नहीं है कि यह मान लिया जाए कि नागरिक प्रक्रिया संहिता हमेशा राजतंत्रीय सरकार द्वारा शासित विदेशी राज्यों के शासकों और रिपब्लिकन सरकार द्वारा शासित राज्यों के शासकों के बीच अंतर करती है। विधानमंडल जिसने संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों को तैयार किया था, वह जानता था कि ऐसे कई राज्य थे जिनमें सरकार का राजशाही स्वरूप प्रचलित नहीं था। सिविल प्रक्रिया संहिता के निर्माताओं की यह मंशा नहीं रही होगी कि राजशाही राज्यों पर मुकदमा चलाया जाए। धारा 86(1) के तहत भारत की नगरपालिका अदालतों में केंद्र सरकार की सहमति के अधीन, जबकि विदेशी राज्य जो इस प्रकार शासित नहीं हैं, उन्हें धारा 86(1) के बाहर आना चाहिए और इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत प्रतिरक्षा का दावा करने में सक्षम

होना चाहिए। जब धारा 87(1)(बी) 1951 में पेश की गई थी तो यह इरादा रहा होगा कि उसमें 'शासक' की परिभाषा में विदेशी राज्यों के सभी मोती शामिल होने चाहिए, चाहे उनकी सरकार किसी भी रूप में हो। [331 ई-एफ]

(iv) धारा 86(1) के प्रावधानों का प्रभाव यह प्रतीत होता है कि यह एक ऐसे क्षेत्र को कवर करने वाला वैधानिक प्रावधान करता है जो अन्यथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत प्रतिरक्षा के सिद्धांत द्वारा कवर किया जाएगा। प्रत्येक संप्रभु राज्य किसी विदेशी राज्य के अधिकारों और देनदारियों के संबंध में अपनी नगरपालिका अदालतों में मुकदमा चलाने के लिए अपने स्वयं के कानून बनाने में सक्षम है। जिस प्रकार एक स्वतंत्र संप्रभु राज्य वैधानिक रूप से मुकदमा करने और मुकदमा दायर करने के लिए अपने अधिकारों और देनदारियों को प्रदान कर सकता है, उसी प्रकार यह विदेशी राज्यों को अपने नगर निगम में मुकदमा चलाने और मुकदमा चलाने के अधिकारों और देनदारियों के लिए प्रदान कर सकता है। ऐसा होने पर यह मानना वैध होगा कि धारा 86(1) का प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा मान्यता प्राप्त प्रतिरक्षा के सिद्धांत को कुछ हद तक संशोधित करना है। यह धारा प्रदान करती है कि विदेशी राज्यों पर केंद्र सरकार की सहमति से भारत की नगरपालिका अदालतों में मुकदमा दायर किया जा सकता है और जब धारा 86(1) के अनुसार ऐसी सहमति प्रदान की जाती है, किसी विदेशी

राज्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत प्रतिरक्षा के सिद्धांत पर भरोसा करना खुला नहीं होगा क्योंकि भारत में नगरपालिका अदालतें नागरिक प्रक्रिया संहिता में निहित वैधानिक प्रावधानों से बंधी होंगी। [333 बी-ई]

चंदूलाल खुशालजी बनाम अवद बिन उमर सुल्तान नवाज जंग बहादुर, आई.एल.आर. 21 बोम. 351 का उल्लेख है।

(v) धारा 86(1) इस प्रकार उन मामलों पर लागू होती है जहां विदेशी राज्यों के शासकों के खिलाफ मुकदमे लाए जाते हैं और विदेशी राज्य इसके दायरे में आते हैं, चाहे उनकी सरकार किसी भी प्रकार की हो। धारा वर्तमान मुकदमे पर लागू होती है, और इसे दायर करने से पहले केंद्र सरकार की सहमति प्राप्त नहीं की गई थी, मुकदमा रोक दिया गया था। [334 बी-सी]

[इस निर्णय को ध्यान में रखते हुए कि धारा 86(आई) ने मुकदमे पर रोक लगा दी है, न्यायालय ने इस प्रश्न से निपटना आवश्यक नहीं समझा कि क्या प्रत्यर्थियों का अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत पूर्ण प्रतिरक्षा का दावा करना उचित था।] [334 सी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 220/1964।

मूल आदेश संख्या 115/1960 से अपील में कलकत्ता उच्च न्यायालय के 17 अप्रैल, 1961 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील।

अपीलार्थी की ओर से आर. चौधरी, एस. मुखर्जी और एस. एन. मुखर्जी।

प्रत्यर्थियों की ओर से बी. सेन, वी. ए. सैयद मुहम्मद, पी. के. दास और पी. के. बोस।

न्यायालय का फैसला मुख्य **न्यायाधीश गजेंद्रगडकर** द्वारा सुनाया गया।

यह अपील अपीलार्थी मिर्जा अली अकबर काशानी द्वारा दो प्रत्यर्थियों, संयुक्त अरब गणराज्य और अर्थव्यवस्था, आपूर्ति, आयात विभाग के खिलाफ दायर एक मुकदमे से उत्पन्न हुई है। काहिरा में मिस्र गणराज्य, कलकत्ता उच्च न्यायालय के मूल पक्ष पर अपने वादपत्र में, अपीलार्थी ने प्रत्यर्थियों से रुपये की क्षति की वसूली का दावा किया। अनुबंध के उल्लंघन के लिए 6,07,346 रु. अपीलार्थी के अनुसार, विचाराधीन अनुबंध 27 मार्च, 1958 को पार्टियों के बीच किया गया था। प्रत्यर्थी संख्या 2, जो अनुबंध का एक पक्ष था, कुछ नियमों और शर्तों पर अपीलार्थी से चाय खरीदने के लिए सहमत हुआ था; इनमें से एक यह था कि प्रत्यर्थी संख्या 2 अनुबंध की अवधि के दौरान भारत में किसी और के साथ चाय की खरीद के लिए कोई और ऑर्डर नहीं देगा और यह, हर मामले में, अपीलार्थी को प्रत्यर्थी के लिए पहले इनकार का लाभ देगा। संख्या 2 की अतिरिक्त आवश्यकताएँ। अपीलार्थी ने आरोप लगाया कि अनुबंध के कार्यकाल के

दौरान, प्रतिवादियों ने अपीलार्थी को उक्त आवश्यकता का पालन करने का मौका दिए बिना गलत तरीके से तीसरे पक्ष को चाय की आपूर्ति का ऑर्डर दिया था। इस प्रकार प्रत्यर्थियों ने अनुबंध की महत्वपूर्ण शर्तों का उल्लंघन किया है।

पूर्व में, मिस्र गणराज्य और सीरिया गणराज्य दो स्वतंत्र संप्रभु राज्य थे। हालाँकि, उन्होंने विलय कर लिया और 22 फरवरी, 1958 को एक नए संप्रभु राज्य का गठन किया। इस नए संप्रभु राज्य को संयुक्त अरब गणराज्य के रूप में जाना जाता है और वर्तमान अपील में इसे प्रत्यर्थी संख्या 1 के रूप में संदर्भित किया गया है। इस नये राज्य को भारत सरकार द्वारा मान्यता दे दी गयी है। प्रत्यर्थी संख्या 2 प्रत्यर्थी संख्या 1 के विभाग के रूप में कार्य कर रहा है और उसका अभिन्न अंग है। वर्तमान मुकदमा 10 अगस्त, 1959 को स्थापित किया गया था। यह सामान्य आधार है कि अपीलार्थी ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 86 के तहत मुकदमा शुरू करने के लिए केंद्र सरकार की सहमति प्राप्त नहीं की थी। हालाँकि, अपीलार्थी ने इस तथ्य के मद्देनजर लेटर्स पेटेंट के खंड 12 के तहत अनुमति के लिए आवेदन किया था कि कार्रवाई के कारण का एक हिस्सा कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न हुआ था। विद्वान विचारण न्यायाधीश द्वारा अपीलार्थी को यह अनुमति प्रदान की गई।

3 दिसंबर, 1959 को, प्रत्यर्थियों ने मुकदमे में उपस्थिति दर्ज कराई; और 17 दिसंबर, 1959 को, उन्होंने एक आदेश के लिए आवेदन किया कि लेटर्स पेटेंट के खंड 12 के तहत दी गई अनुमति को रद्द कर दिया जाना चाहिए, वादी को खारिज कर दिया जाना चाहिए और मुकदमे में आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी जानी चाहिए। प्रत्यर्थियों के अनुसार, विचारण न्यायालय के पास मुकदमे पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था क्योंकि संयुक्त अरब गणराज्य के राष्ट्रपति वहां के शासक थे और मुकदमा वास्तव में, और सार रूप में, उनके खिलाफ एक मुकदमा था और इस तरह, संहिता की धारा 86 के तहत इसे रोक दिया गया था। उनकी ओर से आगे कहा गया कि कार्रवाई के कथित कारण का कोई भी हिस्सा न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न नहीं हुआ था; और इसलिए, खंड 12 के तहत अनुमति नहीं दी जा सकती। इस याचिका की सुनवाई में, प्रत्यर्थियों को अपनी याचिका के समर्थन में एक अतिरिक्त आधार का आग्रह करने की अनुमति दी गई थी कि अनुमति रद्द कर दी जानी चाहिए; उन्होंने आग्रह किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 एक विदेशी संप्रभु राज्य है और इस तरह उसे भारत के नगरपालिका कानून द्वारा अपनाए और लागू किए गए अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियमों के तहत विचारण न्यायालय में मुकदमा चलाने से पूर्ण छूट प्राप्त है।

अपीलार्थी द्वारा इन दलीलों का खंडन किया गया था, यह आग्रह किया गया था कि संहिता की धारा 86 वर्तमान मुकदमे में बाधा नहीं है, क्योंकि उक्त धारा ने केवल एक विदेशी राज्य के शासक के खिलाफ बाधा उत्पन्न की है और वर्तमान मुकदमा उस श्रेणी में स्पष्ट रूप से लागू नहीं होता है। अपीलार्थी के अनुसार, केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना मुकदमा चलाने से छूट किस धारा में है। संदर्भित संहिता के 86 को प्रत्यर्थी संख्या 1 जैसे किसी विदेशी राज्य द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थी ने यह भी आग्रह किया कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जिस लेनदेन ने वर्तमान मुकदमे को जन्म दिया है, उसका सरकारी कार्यों से कोई लेना-देना नहीं है। प्रत्यर्थी संख्या 1, अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांत के तहत प्रत्यर्थियों द्वारा किसी भी छूट का दावा नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थी ने आगे तर्क दिया कि वर्तमान कार्यवाही में उपस्थित होकर और उसके बाद याचिका दायर करके, प्रत्यर्थियों ने न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के प्रति समर्पण कर दिया था और इसके अधिकार क्षेत्र पर अपनी आपत्ति को माफ कर दिया था।

विद्वान विचारण न्यायाधीश ने माना कि धारा 86 वर्तमान मुकदमे पर रोक नहीं लगाती है। उन्होंने अपीलार्थी के इस तर्क को स्वीकार कर लिया कि उस रोक को केवल एक विदेशी राज्य के शासक के खिलाफ ही लागू किया जा सकता है, न कि प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ, जो एक

स्वतंत्र संप्रभु राज्य था। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत प्रत्यर्थियों द्वारा उठाई गई याचिका के सवाल पर, विचारण न्यायाधीश ने कहा कि लेन-देन की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, जिसने वर्तमान मुकदमे को जन्म दिया है, प्रत्यर्थियों द्वारा उठाई गई छूट की दलील को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। छूट के सवाल पर भी उन्होंने प्रत्यर्थियों के खिलाफ पाया। परिणामस्वरूप, प्रत्यर्थियों द्वारा अनुमति रद्द करने के लिए किए गए आवेदन को विचारण न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दिया गया।

इसके बाद प्रत्यर्थियों ने लेटर्स पेटेंट के तहत मामले को कलकत्ता उच्च न्यायालय की अपील अदालत के समक्ष उठाया। अपील न्यायालय का गठन करने वाले दोनों विद्वान न्यायाधीशों ने विचारण न्यायाधीश के निष्कर्ष को बरकरार रखा है। संहिता की धारा 86 वर्तमान मुकदमे के विरुद्ध कोई रोक नहीं लगाती है। हालाँकि, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत प्रत्यर्थियों द्वारा दावा की गई छूट के सवाल के साथ-साथ छूट के सवाल पर विचारण न्यायाधीश के निष्कर्षों को उलट दिया है। उन्होंने माना है कि यह नहीं दिखाया गया है कि मुकदमे पर विचार करने के लिए विचारण न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देने वाले प्रत्यर्थियों द्वारा किए गए आवेदन को उचित रूप से उनके द्वारा न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के प्रति समर्पण के रूप में माना जा सकता है; और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का सिद्धांत जो विदेशी अदालतों में मुकदमा

चलाने से संप्रभु स्वतंत्र राज्यों की पूर्ण प्रतिरक्षा को मान्यता देता है, ने वर्तमान मुकदमे के खिलाफ एक बाधा पैदा की है। परिणामस्वरूप, प्रत्यर्थियों द्वारा की गई अपील की अनुमति दी गई है, विचारण न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया गया है, और अपीलार्थी द्वारा दायर वाद को मास्टर के समन की प्रार्थना (बी) के तहत खारिज कर दिया गया है। अपीलार्थी ने आवेदन किया है और अपील न्यायालय से एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया है और यह उक्त प्रमाण पत्र के साथ है कि वह अपील में इस न्यायालय में आया है।

अपीलार्थी की ओर से श्री आर. चौधरी ने तर्क दिया है कि प्रतिरक्षा के सिद्धांत के दायरे और प्रभाव के बारे में अपील न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण, जिस पर प्रत्यर्थियों ने भरोसा किया था, कानून में गलत है। अपने तर्क के समर्थन में, उन्होंने आग्रह किया है कि हाल के निर्णयों की प्रवृत्ति और हाल के दिनों में अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास की प्रवृत्ति से संकेत मिलता है कि प्रश्न में प्रतिरक्षा के सिद्धांत को अब पूर्ण और अयोग्य सिद्धांत नहीं माना जा सकता है। उनका सुझाव है कि आधुनिक समय में, राज्य वाणिज्यिक लेनदेन में प्रवेश करते हैं और ऐसे वाणिज्यिक लेनदेन को विदेशी देशों में मुकदमा चलाने से संप्रभु राज्यों की प्रतिरक्षा के सिद्धांत की सुरक्षा की अनुमति देना अनुचित होगा। अपने तर्क के समर्थन में, श्री चौधरी ने एच. लॉटरपैच्ट की टिप्पणियों पर बहुत दृढ़ता से भरोसा किया

है, जिन्होंने ओपेनहेम के अंतर्राष्ट्रीय कानून के आठवें संस्करण का संपादन किया है। संपादक लॉटरपैच कहते हैं, "मुकदमे से छूट की अनुमति एक वैध कानूनी दावे के संबंध में कानूनी उपाय से इनकार करने के समान है; इस प्रकार, छूट आपत्ति के लिए खुली है। बाद की परिस्थिति उस चुनौती का कुछ स्पष्टीकरण प्रदान करती है जिसका वह तेजी से सामना कर रही है- इस परिस्थिति के अलावा कि आर्थिक क्षेत्र में आधुनिक राज्य की गतिविधियों के व्यापक विस्तार ने उस नियम को अव्यवहारिक बना दिया है जो एक व्यापारी के रूप में काम करने वाले राज्य को निजी व्यापारियों की तुलना में विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति प्रदान करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अधिकांश राज्यों ने अब विदेशी राज्यों की पूर्ण प्रतिरक्षा के नियम को छोड़ दिया है या छोड़ने की प्रक्रिया में हैं, जिसे आमतौर पर निजी कानून प्रकृति के कृत्यों के रूप में वर्णित किया जाता है। ग्रेट ब्रिटेन में इस संबंध में स्थिति को अस्थिर माना जाना चाहिए" (पृष्ठ 273)।

यहां तक कि डाइसी ने अपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज़ में अयोग्य रूप में ऐसी छूट के संबंध में नियम 17 का प्रतिपादन करते हुए कुछ टिप्पणी की है, जिस पर श्री चौधरी ने हमारा ध्यान आकर्षित किया है। यह सच है कि नियम 17 अन्य बातों के साथ-साथ कहता है कि न्यायालय के पास किसी विदेशी राज्य, या सरकार के प्रमुख या किसी विदेशी राज्य की सरकार के किसी भी विभाग के खिलाफ कार्रवाई या अन्य कार्यवाही पर

विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। इस नियम पर टिप्पणी करते हुए, विद्वान लेखक का मानना है कि "प्रतिरक्षा अंततः सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियमों और उस कानून के सिद्धांत, पार इन पैरेम नॉन हैबेट इम्पेरियम से प्राप्त होती है। सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून का प्रासंगिक नियम अंग्रेजी कानून का हिस्सा बन गया है। हालाँकि, यह असंभव नहीं है कि अंग्रेजी कानून इस संबंध में अंतरराष्ट्रीय कानूनी प्रणाली की मांग से कहीं आगे निकल जाए।" फिर विद्वान लेखक अंग्रेजी निर्णयों का बारीकी से विश्लेषण करता है और निष्कर्ष निकालता है कि ऐसा हो सकता है कि समग्र रूप से अंतर्राष्ट्रीय कानून की प्रणाली क्षेत्राधिकार संबंधी उन्मुक्तियों की एक "कार्यात्मक" अवधारणा की ओर बढ़ रही है, जो उनके दायरे को गतिविधि के क्षेत्र के भीतर के मामलों तक ही सीमित रखेगी, जो अनिवार्य रूप से किसी भी श्रेणी के उस प्रणाली के व्यक्ति से संबंधित हो[1]। श्री चौधरी स्वाभाविक रूप से डाइसी की इन टिप्पणियों पर जोर देते हैं। उन्होंने स्वीकार किया है कि इस मुद्दे पर अंग्रेजी निर्णयों में बताई गई आम सहमति उनके पक्ष में नहीं है, हालांकि *रहीमटोला* बनाम *हैदराबाद के निज़ाम*[2] में लॉर्ड डेनिंग द्वारा उठाई गई असहमति की आवाज़ स्पष्ट रूप से श्री चौधरी की दलील का समर्थन करती है। संक्षेप में, श्री चौधरी ने

1 डाइसीज़ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ़ लॉज़, 7 वां संस्करण, पृष्ठ 132-33।

2 [1958] ए.सी. 379

अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत संप्रभु राज्यों की प्रतिरक्षा के बारे में दिलचस्प सवाल पर अपना मामला प्रस्तुत करने का प्रयास किया है।

जब हम इस बिंदु पर श्री चौधरी को सुन रहे थे, हमने उनसे पूछा कि क्या नीचे की अदालतों के इस निष्कर्ष का समर्थन किया जाए कि वर्तमान मुकदमा संहिता की धारा 86 के तहत वर्जित नहीं है और उन्होंने तर्क दिया कि उनका मामला यह था कि वह निष्कर्ष स्पष्ट रूप से सही था और वर्तमान अपील को इस आधार पर निपटाया जाना चाहिए कि धारा 86 ने अपीलार्थी के खिलाफ कोई कठिनाई पैदा नहीं की। श्री चौधरी ने छूट के प्रश्न पर अपील न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष की सत्यता पर विवाद नहीं किया।

हालाँकि, प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित हुए श्री बी. सेन ने आग्रह किया कि वह संहिता की धारा 86 की प्रयोज्यता के संबंध में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष की सत्यता को चुनौती देना चाहते हैं। उन्होंने माना कि विचारण न्यायाधीश के साथ-साथ लेटर्स पेटेंट अपील की सुनवाई करने वाले दो विद्वान न्यायाधीश भी इस बात पर सहमत हुए थे कि धारा 86 वर्तमान मुकदमे के विरुद्ध कोई बाधा नहीं थी; लेकिन श्री सेन का तर्क यह था कि उक्त निष्कर्ष धारा 86 के वास्तविक दायरे और प्रभाव के साथ स्पष्ट रूप से असंगत था। उन्होंने यह भी आग्रह

किया कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत प्रतिरक्षा के सिद्धांत की प्रयोज्यता के संबंध में अपील न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण सही था।

इस अपील की सुनवाई के दौरान, यह स्पष्ट हो गया कि दो प्रश्नों पर हमें विचार करना है; पहला संहिता की धारा 86 के अनुप्रयोग के संबंध में है और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत प्रतिरक्षा के सिद्धांत के दायरे और प्रभाव के संबंध में। तार्किक रूप से, सबसे पहले संहिता की धारा 86 के प्रभाव पर विचार करना होगा, क्योंकि यह सामान्य आधार है कि यदि हमें इसे धारण करना है कि धारा 86 वर्तमान मुकदमे के लिए एक बाधा थी, फिर अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत प्रतिरक्षा के बारे में दिलचस्प बिंदु पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। उस दृष्टि से, अपील इस आधार पर खारिज कर दी जाएगी कि मुकदमा धारा 86 द्वारा वर्जित था। श्री चौधरी और श्री सेन दोनों को सुनने के बाद, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश, सम्मानपूर्वक, ऐसा मानने में गलत थे कि वर्तमान मुकदमे के विरुद्ध धारा 86 कोई बाधा उत्पन्न नहीं करती है। यह हमारा विचार है, हम इस पर विचार करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं कि क्या अपील न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत पूर्ण प्रतिरक्षा की उत्तरदाताओं की याचिका को बरकरार रखने में सही था। इसलिए, हमें संहिता की धारा 86 के तहत उठाई गई समस्या से निपटना चाहिए।

प्रासंगिक प्रावधान संहिता की धारा 83-87 बी में पाए जाते हैं। इन प्रावधानों का शीर्षक है "विदेशियों द्वारा और विदेशी शासकों, राजदूतों और दूतों द्वारा या उनके विरुद्ध मुकदमे"। वर्तमान धाराएं सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1951 (संख्या II/1951) की धारा 12 द्वारा पेश की गई हैं। संशोधन से पहले, प्रासंगिक धाराएँ 83-87 थीं। संशोधन के परिणामस्वरूप पूर्व भारतीय राज्यों के शासकों के मामलों को अब धारा 87 बी द्वारा निपटाया जाता है, और शेष प्रावधान विदेशी राज्यों और विदेशी राज्यों के शासकों से संबंधित हैं। यह इतिहास की बात है कि भारतीय राज्यों के शासक जो 1908 की संहिता के तहत धारा 84 और 86 में निहित प्रावधानों के लाभ का दावा कर सकते थे, वे शासक नहीं रहे और अब पूर्व भारतीय राज्यों के शासकों के रूप में वर्णित होने के हकदार हैं। इसीलिए धारा 87 बी द्वारा पूर्व भारतीय राज्यों के शासकों के संबंध में एक विशिष्ट और अलग प्रावधान किया गया है। मोटे तौर पर कहा गया है कि, पिछली धारा 83-87 और वर्तमान धारा 83-87 बी की योजनाओं के बीच मुख्य अंतर है।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों ने उत्तरदाताओं के तर्क को खारिज कर दिया है कि वर्तमान मुकदमे को संहिता की धारा 86 के तहत वर्जित किया गया है, ऐसा प्रतीत होता है कि धारा 86(1) एक विदेशी राज्य के शासक को संदर्भित करती है न कि किसी विदेशी राज्य

को। हम वर्तमान में प्रासंगिक अनुभागों का हवाला देंगे और उनका अर्थ लगाएंगे; लेकिन, फिलहाल, हम उस मुख्य आधार का संकेत दे रहे हैं जिस पर विद्वान न्यायाधीशों का निर्णय आधारित है। धारा 86 (1) कहती है कि केंद्र सरकार की सहमति के बिना किसी भी शासक पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता; और विद्वान न्यायाधीशों ने सोचा कि एक शासक को एक राज्य से अलग किया जाना चाहिए और धारा 86(1) को राज्य के मामले में विस्तारित नहीं किया जा सकता है। धारा 86(1) द्वारा दिए गए एक शासक के संदर्भ की तुलना धारा 84 में किए गए एक विदेशी राज्य के संदर्भ से की गई थी; और इस विरोधाभास को इस निष्कर्ष के समर्थन में लागू किया गया कि धारा 86 को किसी विदेशी राज्य के खिलाफ लागू नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार, धारा 86(3) केंद्र सरकार की सहमति के बिना किसी शासक को गिरफ्तारी से छूट देती है। एक समान तर्क किसी विदेशी राज्य के मामले को धारा 86 के दायरे से बाहर ले जाने के इस प्रावधान पर आधारित है। इसी तरह, धारा 85 एक शासक को संदर्भित करती है, जबकि केंद्र सरकार को ऐसे शासक की ओर से कार्य करने के लिए किसी भी व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए अधिकृत किया जाता है, और कहा जाता है कि उनका प्रावधान इस तथ्य को भी सामने लाता है कि किसी विदेशी राज्य के शासक को राज्य से अलग माना जाता है।

विद्वान न्यायाधीशों के निर्णयों से ऐसा प्रतीत होता है कि वे यह मानने के लिए तैयार थे कि एक ऐसे राज्य के संबंध में जो सरकार के राजतंत्रीय स्वरूप द्वारा शासित होता है, उस राज्य और उसके शासक के बीच अंतर करना स्वीकार्य नहीं होगा; और इसलिए, यह सोचा गया कि एक राजशाही राज्य के संबंध में, धारा 86 संभावित रूप से लागू हो सकती है, हालांकि धारा 86(1) में प्रयुक्त शब्द, किसी राज्य को संदर्भित नहीं करते हैं। इस दृष्टिकोण पर, अपील न्यायालय ने स्वाभाविक रूप से अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रावधानों के तहत प्रत्यर्थियों की प्रतिरक्षा के बारे में प्रश्न पर विचार किया। इस प्रकार हमारे निर्णय के लिए जो मुद्दा उठता है वह एक संकीर्ण दायरे में आता है; क्या कलकत्ता उच्च न्यायालय का यह मानना सही था कि वर्तमान मुकदमा धारा 86(1) के दायरे में नहीं आता है? यह स्पष्ट है कि यदि इस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक है, तो मुकदमा गलत होगा क्योंकि यह केंद्र सरकार की सहमति के बिना दायर किया गया है।

इस प्रश्न का निर्णय मुख्यतः धारा 86(1) के निर्माण पर ही निर्भर करता है; लेकिन उक्त धारा का अर्थ निकालने से पहले धारा 84 का विचारण करना आवश्यक है। वर्तमान धारा 84 इस प्रकार है:-

> "एक विदेशी राज्य किसी भी सक्षम न्यायालय में मुकदमा कर सकता है: बशर्ते कि मुकदमे का उद्देश्य ऐसे राज्य के शासक या ऐसे राज्य के किसी भी अधिकारी में

उसकी सार्वजनिक क्षमता में निहित निजी अधिकार को लागू करना है।"

1882 की संहिता में इस धारा की पूर्ववर्ती धारा 431 थी; जिसे इस प्रकार पढ़ा गया:-

"एक विदेशी राज्य ब्रिटिश भारत के न्यायालयों में मुकदमा कर सकता है, बशर्ते-

(ए) इसे महामहिम या काउंसिल में गवर्नर-जनरल द्वारा मान्यता दी गई है, और

(बी) मुकदमे का उद्देश्य विदेशी राज्य के प्रमुख या जनता के निजी अधिकारों को लागू करना है।

न्यायालय इस तथ्य का न्यायिक नोटिस लेगा कि विदेशी राज्य को महामहिम या परिषद में गवर्नर-जनरल द्वारा मान्यता नहीं दी गई है।"

1908 में धारा 84(1) ने धारा 431 का स्थान ले लिया। इस धारा को अधिनियमित करते समय धारा की संरचना में एक संशोधन किया गया तथा इसमें दो परन्तुक जोड़े गये। हम वर्तमान में उस उद्देश्य का उल्लेख करेंगे जिसे दूसरे परंतुक द्वारा पूरा करने का इरादा था।

यह स्पष्ट है कि धारा 84 किसी विदेशी राज्य को मुकदमा करने का अधिकार देती है। दूसरे शब्दों में, यह विदेशी राज्य को मुकदमा दायर करने का अधिकार प्रदान करता है, जबकि धारा 86 किसी विदेशी राज्य के शासक पर केंद्रीय सरकार की सहमति से मुकदमा दायर करने का दायित्व या दायित्व लगाती है। यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि इन अनुभागों का शीर्षक किसी भी तरह से विदेशी राज्यों को संदर्भित नहीं करता है, धारा 84 एक विदेशी राज्य को एक सक्षम न्यायालय में मुकदमा लाने का अधिकार देती है। यह स्पष्ट है कि धारा 84 किसी विदेशी राज्य को मुकदमा करने का अधिकार देती है। दूसरे शब्दों में, यह विदेशी राज्य को मुकदमा दायर करने का अधिकार प्रदान करता है, जबकि धारा 86 किसी विदेशी राज्य के शासक पर केंद्रीय सरकार की सहमति से मुकदमा दायर करने का दायित्व या दायित्व लगाती है। यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि इन अनुभागों का शीर्षक किसी भी तरह से विदेशी राज्यों को संदर्भित नहीं करता है, धारा 84 एक विदेशी राज्य को एक सक्षम न्यायालय में मुकदमा लाने का अधिकार देती है। यह सच है कि धाराओं के शीर्षकों के महत्व पर बहुत अधिक जोर नहीं दिया जा सकता है; लेकिन, दूसरी ओर, प्रासंगिकता पर विवाद नहीं किया जा सकता है; और इसलिए, हमें ऐसा लगता है कि विधानमंडल ने यह नहीं सोचा था कि किसी विदेशी राज्य के मामले को धाराओं के इस समूह के शीर्षक के तहत शामिल नहीं किया जाएगा।

इस संबंध में, यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि जब किसी राज्य का शासक मुकदमा करता है या मुकदमा दायर किया जाता है, तब भी मुकदमा राज्य के नाम पर होना चाहिए; यह धारा 87 के प्रावधान का प्रभाव है, ताकि यह अनुमान लगाना वैध हो सके कि धारा 84, 86 और 87 को एक साथ पढ़ने का प्रभाव यह होगा कि मुकदमा राज्य के नाम पर होगा, चाहे वह धारा 84 के तहत किसी विदेशी राज्य द्वारा दायर किया गया मुकदमा हो, या धारा 86 के तहत किसी विदेशी राज्य के शासक के खिलाफ मुकदमा हो। प्रक्रिया के तौर पर, किसी विदेशी राज्य के शासक और उस विदेशी राज्य, जिसका वह शासक है, के बीच तीव्र अंतर करना स्वीकार्य नहीं होगा। प्रक्रिया के प्रयोजन के लिए, प्रत्येक मामले में मुकदमा किसी राज्य के नाम पर होना चाहिए। यह एक और कारक है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

फिर उस मुकदमे के दायरे के संबंध में जो किसी विदेशी राज्य द्वारा धारा 84 के तहत दायर किया जा सकता है, परंतुक यह स्पष्ट करता है कि जो मुकदमा किसी विदेशी राज्य द्वारा दायर किया जा सकता है, वह ऐसे राज्य के शासक या ऐसे राज्य के किसी अधिकारी में उसकी सार्वजनिक क्षमता में निहित निजी अधिकार को लागू करने के लिए होना चाहिए। यह याद किया जाएगा कि 1882 की संहिता की धारा 431 (बी) में यह प्रावधान किया गया था कि धारा 431 के तहत दायर किए जा सकने वाले

मुकदमे का उद्देश्य विदेशी राज्य के प्रमुख या विषयों के निजी अधिकारों को लागू करना है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस खंड ने कुछ संदेह को जन्म दिया है कि क्या किसी विदेशी राज्य द्वारा उस राज्य के विषयों के निजी अधिकारों के संबंध में मुकदमा लाया जा सकता है; और उक्त संदेह को दूर करने के लिए, 1908 की संहिता ने धारा 84(1) में दूसरा परंतुक डाला, जिसने 1882 की संहिता की धारा 431 का स्थान ले लिया। इस परंतुक ने यह स्पष्ट कर दिया कि किसी विदेशी राज्य द्वारा मुकदमेबाजी का उद्देश्य किसी निजी विषय जैसे किसी विषय में निहित अधिकार को लागू करना नहीं हो सकता है; यह किसी राज्य के प्रमुख या ऐसे राज्य के किसी अधिकारी में उसकी सार्वजनिक क्षमता में निहित निजी अधिकार का प्रवर्तन होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, जो मुकदमा धारा 84 के तहत दायर किया जा सकता है और जो 1882 की संहिता की धारा 431 के तहत दायर किया जा सकता था, वह राज्य के प्रमुख या विषयों अर्थात उक्त राज्य के कुछ सार्वजनिक अधिकारियों में निहित निजी अधिकार से संबंधित होना चाहिए। किसी व्यक्ति का निजी अधिकार, जिसे राज्य के निजी अधिकार से अलग कहा जाता है, किसी भी स्तर पर नागरिक प्रक्रिया संहिता के तहत किसी विदेशी राज्य द्वारा मुकदमे का विषय-वस्तु नहीं था।

यह हमें इस प्रश्न पर ले जाता है कि "निजी अधिकार" शब्द का सही अर्थ क्या है। "निजी अधिकार" शब्दों की व्याख्या करते समय इस तथ्य

को ध्यान में रखना आवश्यक है कि मुकदमा एक विदेशी राज्य द्वारा है; और इस संदर्भ में, राज्य के निजी अधिकारों को राजनीतिक अधिकारों से अलग किया जाना चाहिए। यह विरोधाभास राजनीतिक निकाय के अधिकारों के विपरीत निजी अधिकारों या व्यक्तिगत अधिकारों के बीच नहीं है: यह विरोधाभास राज्य के निजी अधिकारों के बीच है जो उसके राजनीतिक या क्षेत्रीय अधिकारों से अलग है। यह स्पष्ट है कि किसी विदेशी राज्य द्वारा दावा किए गए सभी अधिकार, जो राजनीतिक और क्षेत्रीय चरित्र के हैं, एक राज्य और दूसरे के बीच समझौते द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत तय किए जा सकते हैं। वे किसी विदेशी राज्य की नगरपालिका अदालतों में मुकदमे की विषय-वस्तु नहीं हो सकते है। इस प्रकार, परंतुक में जिस निजी अधिकार का उल्लेख है, वह अंतिम विश्लेषण के अनुसार, राज्य में निहित अधिकार है; यह किसी राज्य के शासक या ऐसे राज्य के किसी अधिकारी में उसकी सार्वजनिक क्षमता में निहित हो सकता है; लेकिन यह एक ऐसा अधिकार है जो वास्तव में और मूलतः राज्य में निहित है। यह ऐसे अधिकार के संबंध में है कि एक विदेशी राज्य धारा 84 के तहत मुकदमा लाने के लिए अधिकृत है।

हाजोन मनिक बनाम *बर सिंग*[3] मामले में, कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1882 की धारा 431, खंड (बी) में बोले गए "निजी अधिकार" शब्दों के अर्थ पर विचार करने का अवसर

3 II खंड 17

मिला था, और यह माना गया कि उक्त शब्दों का अर्थ राजनीतिक निकाय या राज्य के विपरीत व्यक्तिगत अधिकार नहीं है, बल्कि राज्य के वे निजी अधिकार हैं जिन्हें न्यायालय में लागू किया जाना चाहिए, जैसा कि उसके राजनीतिक या क्षेत्रीय अधिकारों से अलग है, जो अपने स्वभाव से ही, इसे एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच व्यवस्था का विषय बनाया जाना चाहिए। वे ऐसे अधिकार हैं जिन्हें किसी विदेशी राज्य द्वारा निजी व्यक्तियों के विरुद्ध लागू किया जा सकता है, जो उन अधिकारों से अलग हैं जो एक राज्य को अपनी राजनीतिक क्षमता में दूसरे राज्य के विरुद्ध प्राप्त हो सकते हैं।

यह हमें धारा 86 तक ले जाता है। धारा 86(1) जिससे हमारा सीधा संबंध है, इस प्रकार है:-

> "किसी विदेशी राज्य के किसी भी शासक पर उस सरकार के सचिव द्वारा लिखित रूप में प्रमाणित केंद्र सरकार की सहमति के अलावा मुकदमा चलाने के लिए अन्यथा सक्षम किसी भी अदालत में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।"

इस धारा में एक प्रावधान है जिससे हमें वर्तमान अपील में कोई सरोकार नहीं है। धारा 86(2) सहमति के प्रश्न से संबंधित है जिसे देने के लिए केंद्र सरकार अधिकृत है, और यह बताती है कि सहमति कैसे दी जा

सकती है और उन मामलों का भी प्रावधान करती है जिनमें ऐसी सहमति नहीं दी जाएगी। धारा 86(3) गिरफ्तारी के प्रश्न को संदर्भित करती है और प्रावधान करती है कि किसी विदेशी राज्य के किसी भी शासक को केंद्र सरकार की सहमति के बिना गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और ऐसे किसी भी शासक की संपत्ति के खिलाफ कोई डिक्री निष्पादित नहीं की जाएगी। धारा 86(4) धारा 86 के पूर्ववर्ती प्रावधानों को खंड (ए), (बी) और (सी) में निर्दिष्ट अधिकारियों की तीन श्रेणियों तक विस्तारित करती है।

धारा 86(1) जैसा कि 1951 के संशोधन से पहले थी, इस प्रकार पढ़ें:-

> "ऐसा कोई भी राजकुमार या प्रमुख, और किसी विदेशी राज्य का कोई राजदूत या दूत, केंद्र सरकार की सहमति से, हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित कर सकता है उस सरकार के सचिव के खिलाफ, लेकिन ऐसी सहमति के बिना, किसी भी सक्षम न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।"

जहां तक अन्य प्रावधानों का सवाल है, संशोधन अधिनियम द्वारा कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया गया है। हालाँकि धारा का स्वरूप और इसकी संरचना बदल दी गई है।

इसके बाद धारा 87 आती है जिसका उल्लेख हम पहले ही कर चुके हैं। इस धारा में प्रावधान है कि किसी विदेशी राज्य का शासक अपने राज्य

के नाम पर मुकदमा कर सकता है और उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। वर्तमान धारा का यह प्रावधान काफी हद तक धारा 87 के समान है जो 1908 की संहिता में हुआ था। उक्त धारा में प्रावधान है कि एक संप्रभु राजकुमार या शासक प्रमुख अपने राज्य के नाम पर मुकदमा कर सकता है और मुकदमा किया जाएगा। यह प्रावधान स्वाभाविक रूप से धारा 86(1) के अनुरूप है जैसा कि तब था।

धारा 87 ए(1) जिसे 1951 के संशोधन अधिनियम द्वारा पहली बार जोड़ा गया है, "विदेशी राज्य" और "शासक" की परिभाषाएँ निर्धारित करता है।धारा 87 ए(1)(ए) में प्रावधान है कि इस भाग में, "विदेशी राज्य" का अर्थ भारत के बाहर कोई भी राज्य है जिसे केंद्र सरकार द्वारा मान्यता दी गई है; और (बी) किसी विदेशी राज्य के संबंध में "शासक" का अर्थ वह व्यक्ति है जिसे उस समय केंद्र सरकार द्वारा उस राज्य का प्रमुख माना जाता है।

धारा 86 की ओर लौटते हुए, यह मानने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती कि जब धारा 86(1) किसी विदेशी राज्य के शासक को संदर्भित करती है, यह उक्त राज्य के संबंध में शासक को संदर्भित करता है, और इसका मतलब उस व्यक्ति से है जिसे उस समय केंद्र सरकार द्वारा उस राज्य का प्रमुख माना जाता है। धारा 87 ए(1)(बी) द्वारा निर्धारित परिभाषा के मद्देनजर, इस तर्क को स्वीकार करना मुश्किल लगता है कि धारा 86(1)

के तहत "किसी विदेशी राज्य के शासक" की अभिव्यक्ति केवल विदेशी राज्यों के शासकों के मामलों में ही हो सकती है जो सरकार के राजशाही स्वरूप द्वारा शासित होते हैं। विदेशी शासक की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि जब धारा 86(1) विदेशी राज्यों के शासकों को संदर्भित करती है, तो यह सभी विदेशी राज्यों के शासकों को संदर्भित करती है, चाहे उनकी सरकार किसी भी प्रकार की हो। यदि किसी विदेशी राज्य में प्रचलित सरकार का स्वरूप गणतांत्रिक है, तो उक्त राज्य का शासक वह व्यक्ति होगा जिसे केंद्र सरकार द्वारा उस समय के लिए उस राज्य के प्रमुख के रूप में मान्यता दी गई हो। दूसरे शब्दों में, एक शासक की परिभाषा स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि जो कोई भी किसी विदेशी राज्य के प्रमुख के रूप में मान्यता प्राप्त है, वह धारा 86 के तहत एक विदेशी राज्य के शासक के विवरण में आएगा। ऐसा होने पर, हमें नहीं लगता कि धारा 86(1) को पढ़ने में, किसी भी सीमा की शर्तों को आयात करने की अनुमति होगी; और जब तक धारा 86(1) की व्याख्या में सीमा की कुछ शर्तों को शामिल नहीं किया जाता, तब तक इस तर्क को बरकरार नहीं रखा जा सकता कि एक रिपब्लिकन राज्य का प्रमुख उस राज्य का शासक नहीं है।

इसके अलावा, सिद्धांत रूप में, यह समझना आसान नहीं है कि यह क्यों माना जाना चाहिए कि नागरिक प्रक्रिया संहिता हमेशा राजशाही

सरकार द्वारा शासित विदेशी राज्यों के शासकों और रिपब्लिकन सरकार द्वारा शासित राज्यों के शासकों के बीच अंतर करती है। सरकार के दोनों रूप पिछले कई वर्षों से अस्तित्व में हैं, और विधानमंडल, जिसने संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों को तैयार किया था, को पता था कि ऐसे कई राज्य हैं जिनमें सरकार का राजतंत्रीय स्वरूप प्रचलित नहीं है। क्या सिविल प्रक्रिया संहिता के निर्माताओं का यह इरादा रहा होगा कि राजशाही राज्यों पर भारत की नगरपालिका अदालतों में, केंद्र सरकार की सहमति के अधीन, धारा 86(1) के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए, जबकि विदेशी राज्य जो इस प्रकार शासित नहीं हैं, उन्हें धारा 86(1) के बाहर आना चाहिए और इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत प्रतिरक्षा का दावा करने में सक्षम होना चाहिए? हमारी राय में, कोई वैध आधार नहीं सुझाया गया है कि इस प्रश्न का उत्तर सकारात्मक क्यों दिया जाना चाहिए।

इस संबंध में एक और परिस्थिति है जिसका हम उल्लेख कर सकते हैं। हमने पहले ही देखा है कि प्रावधानों में संशोधन करते समय, 1951 के संशोधन अधिनियम में धारा 87 बी के तहत पूर्व भारतीय राज्यों के शासकों के प्रश्न पर अलग से विचार किया गया है, और बाकी प्रावधानों में कुछ औपचारिक और कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए, विधानमंडल ने धारा 87 ए पेश की है जो एक परिभाषा धारा है। उस समय जब धारा 87 ए(1)(बी) में "शासक" को परिभाषित किया गया था, विधायिका के लिए यह स्पष्ट

होना चाहिए कि यह परिभाषा विदेशी राज्यों के सभी प्रमुखों को ध्यान में रखेगी, चाहे उनमें सरकार का स्वरूप कुछ भी हो; और इसलिए, इसे धारण करना अनुचित नहीं होगा कि परिभाषा का उद्देश्य यह स्पष्ट करना था कि जिन विदेशी राज्यों के शासकों पर धारा 86(1) लागू होती है, वे सभी विदेशी राज्यों के शासकों को कवर करेंगे, बशर्ते वे धारा 87 ए(1)(बी) की परिभाषा की आवश्यकताओं को पूरा करते हों।

संयोग से, हम धारा 86(1) पर जो निर्माण करना चाहते हैं वह इस बिंदु पर संहिता की योजना के साथ सामंजस्यपूर्ण है। धारा 84 एक विदेशी राज्य को उन अधिकारों के संबंध में मुकदमा करने के लिए अधिकृत करती है जिनके लिए इसका परंतुक संदर्भित है। विदेशी राज्यों को उक्त अधिकार प्रदान करने के बाद, धारा 86(1) विदेशी राज्यों के विरुद्ध एक सीमित दायित्व निर्धारित करने के लिए आगे बढ़ती है। मुकदमा चलाने के लिए विदेशी राज्यों के दायित्व की सीमा दोगुनी है। पहली सीमा यह है कि इस तरह का मुकदमा केंद्र सरकार की उस सरकार के सचिव द्वारा लिखित रूप में प्रमाणित सहमति के बिना शुरू नहीं किया जा सकता है। यह आवश्यकता विदेशी राज्यों को तुच्छ या अनुचित दावों से बचाने के लिए विधानमंडल की चिंता को दर्शाती है। दूसरी सीमा यह है कि केंद्र सरकार तब तक सहमति नहीं देगी जब तक केंद्र सरकार को यह न लगे कि मामला धारा 86(2) के खंड (ए) से (डी) में से किसी एक के अंतर्गत

आता है। दूसरे शब्दों में, विधानमंडल ने केंद्र सरकार को पर्याप्त मार्गदर्शन दिया है ताकि उक्त सरकार इस प्रश्न पर निर्णय ले सके कि किसी विदेशी राज्य के शासक के खिलाफ दायर किए जाने वाले मुकदमे पर सहमति कब दी जानी चाहिए। मुकदमा दायर करने के लिए इस सीमित दायित्व का प्रावधान करने के बाद, विधायिका ने किसी विदेशी राज्य के शासक को गिरफ्तारी से बचाने का ध्यान रखा है, सिवाय इसके कि केंद्र सरकार की सहमति से प्रमाणित किया जाए और निर्देश दिया है कि ऐसे किसी भी शासक की संपत्ति के विरुद्ध कोई डिक्री निष्पादित नहीं की जाएगी; यह धारा 86(3) का प्रभाव है।

यह सच है कि यह प्रावधान ऐसे किसी भी शासक की संपत्ति को किसी भी शासक के खिलाफ पारित किए जाने वाले किसी भी डिक्री के निष्पादन से छूट देता है; और जाहिरा तौर पर, उच्च न्यायालय ने सोचा कि इससे यह पता चलता है कि धारा 86(1) के तहत किसी विदेशी राज्य के शासक को स्वयं शासक होना चाहिए न कि राज्य का। हमारी राय में, यह दृष्टिकोण उचित नहीं है। यह प्रावधान कि किसी विदेशी राज्य के शासक के विरुद्ध पारित डिक्री को ऐसे शासक की संपत्ति के विरुद्ध निष्पादित नहीं किया जाएगा, बल्कि यह दर्शाता है कि जो छूट दी गई है वह स्वयं शासक की अलग संपत्ति है, न कि राज्य के प्रमुख के रूप में शासक की संपत्ति। जिस राज्य का शासक मुखिया माना जाता है, उसकी

संपत्ति और शासक की व्यक्तिगत संपत्ति के बीच अंतर किया जाता है। इसलिए, हम इस बात से संतुष्ट हैं कि धारा 86(1) उन मामलों पर लागू होती है जहां विदेशी राज्यों के शासकों के खिलाफ मुकदमे लाए जाते हैं और विदेशी राज्य इसके दायरे में आते हैं, चाहे उनकी सरकार किसी भी प्रकार की हो। हमने पहले ही संकेत दिया है कि जब भी किसी विदेशी राज्य के शासक द्वारा या उसके खिलाफ कोई मुकदमा दायर करने का इरादा होता है, तो यह राज्य के नाम पर होना चाहिए, और वास्तव में, वर्तमान मुकदमा इसी तरह दायर किया गया है।

धारा 86(1) के प्रावधानों का प्रभाव यह प्रतीत होता है कि यह एक ऐसे क्षेत्र को समाहित करने वाला वैधानिक प्रावधान करता है जो अन्यथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत प्रतिरक्षा के सिद्धांत द्वारा समाहित किया जाएगा। यह विवादित नहीं है कि प्रत्येक संप्रभु राज्य विदेशी राज्यों के अधिकारों और देनदारियों के संबंध में अपने स्वयं के नगरपालिका न्यायालयों में मुकदमा चलाने के लिए अपने स्वयं के कानून बनाने में सक्षम है। जिस तरह एक स्वतंत्र संप्रभु राज्य वैधानिक रूप से मुकदमा करने और मुकदमा चलाने के लिए अपने अधिकारों और देनदारियों को प्रदान कर सकता है, उसी तरह यह विदेशी राज्यों को अपनी नगरपालिका अदालतों में मुकदमा चलाने और मुकदमा चलाने के अधिकारों और देनदारियों के लिए प्रदान कर सकता है। ऐसा होने पर, यह मानना वैध होगा कि धारा 86(1) का प्रभाव

अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा मान्यता प्राप्त प्रतिरक्षा के सिद्धांत को कुछ हद तक संशोधित करना है। यह धारा प्रदान करती है कि विदेशी राज्यों पर केंद्र सरकार की सहमति से भारत की नगरपालिका अदालतों में मुकदमा दायर किया जा सकता है और जब धारा 86(1) के अनुसार ऐसी सहमति प्रदान की जाती है, तो किसी विदेशी राज्य पर भरोसा करना संभव नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत प्रतिरक्षा का सिद्धांत, क्योंकि भारत में नगरपालिका अदालतें वैधानिक प्रावधानों से बंधी होंगी, जैसे कि नागरिक प्रक्रिया संहिता में निहित। संक्षेप में, धारा 86(1) केवल प्रक्रियात्मक नहीं है; यह एक तरह से धारा 84 का प्रतिरूप है। जबकि धारा 84 किसी विदेशी राज्य को मुकदमा करने का अधिकार प्रदान करती है, धारा 86(1) वस्तुतः विदेशी राज्यों पर मुकदमा दायर करने का दायित्व थोपती है, हालांकि यह दायित्व इसके द्वारा निर्धारित सीमाओं से घिरा और सुरक्षित है। वह धारा 86(1) का प्रभाव है।

चंदूलाल खुशालजी बनाम *अवेड बिन उमर सुल्तान नवाज जंग बहादुर*[4] के मामले में, **स्ट्रेची, जे.** को 1882 की संहिता की धारा 433 के प्रावधानों के संबंध में मामले के इस पहलू पर विचार करने का अवसर मिला। विद्वान न्यायाधीश ने कहा, धारा 433 क्या करती है, "संप्रभु राजकुमारों और शासक प्रमुखों और उनके राजदूतों और दूतों के लिए एक व्यक्तिगत विशेषाधिकार बनाना है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों के

4 आई.एल.आर. 21 बॉम्बे 351 पृष्ठ 371-2 पर।

अनुसार, इंग्लैंड में न्यायालयों में स्वतंत्र संप्रभुओं और उनके राजदूतों द्वारा प्राप्त पूर्ण विशेषाधिकार का एक संशोधित रूप है। अंतर यह है कि जहां इंग्लैंड में विशेषाधिकार बिना शर्त है, केवल संप्रभु या उसके प्रतिनिधि की इच्छा पर निर्भर है, वहीं भारत में यह काउंसिल में गवर्नर जनरल की सहमति पर निर्भर है, जो केवल निर्दिष्ट शर्तों के तहत दिया जा सकता है। हालाँकि, यह संशोधित या सशर्त विशेषाधिकार अनिवार्य रूप से पूर्ण विशेषाधिकार के समान सिद्धांत पर आधारित है, शासक की गरिमा और स्वतंत्रता, जो किसी भी व्यक्ति को अपनी मर्जी से मुकदमा चलाने की अनुमति देने से खतरे में पड़ जाएगी, और इसके परिणामस्वरूप राजनीतिक असुविधाएँ और जटिलताएँ होंगी"। हमारा यह मानना है कि यह दृष्टिकोण धारा 433 के प्रावधानों के परिणाम का उतना ही सही प्रतिनिधित्व करता है जितना कि धारा 86(1) में निहित है।

हमारे निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए कि धारा 86(1) वर्तमान मुकदमे पर लागू होती है, यह इस प्रकार है कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित सहमति के अभाव में, मुकदमे पर विचार नहीं किया जा सकता है। मामले के उस दृष्टिकोण पर, दूसरे प्रश्न से निपटना आवश्यक नहीं है कि क्या प्रत्यर्थियों का अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत पूर्ण प्रतिरक्षा का दावा करना उचित था। यह सामान्य आधार है कि यदि कोई विशिष्ट वैधानिक प्रावधान है जैसे कि धारा 86(1) में निहित है जो कुछ शर्तों के अधीन किसी विदेशी

राज्य के खिलाफ मुकदमा दायर करने की अनुमति देता है, तो यह उक्त वैधानिक प्रावधान है जो निर्णय को नियंत्रित करेगा सवाल यह है कि मुकदमा ठीक से दायर किया गया है या नहीं। ऐसे प्रश्न से निपटने में, क़ानून के प्रावधानों से परे जाना अनावश्यक है, क्योंकि क़ानून मुकदमे की गंभीरता को निर्धारित करता है।

परिणाम यह होता है कि अपील विफल हो जाती है और खारिज कर दी जाती है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हम उस आधार पर अपील न्यायालय के निर्णय की पुष्टि कर रहे हैं जो उस न्यायालय के समक्ष सफल नहीं हुआ, हम निर्देश देते हैं कि पक्षों को पूरी लागत स्वयं वहन करनी होगी।

अपील खारिज कि जाती है।

[यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल **'सुवास'** की सहायता से **अनुवादक राहुल कुमार** द्वारा किया गया है।**]**

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।